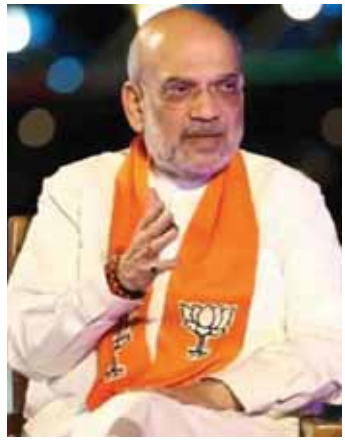


पाक अधिकृत कश्मीर भारत में एकीकरण

पाक अधिकृत कश्मीर-पीओके के भारत में एकीकरण का मुद्दा भाजपा नेता चुनाव अभियान में उठा रहे हैं। 2019 में भाजपा ने पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' को अपनी सरकार की उपलब्धि की तरह पेश किया था। पाक अधिकृत कश्मीर-पीओके पर भारत के दावे पर भाजपा ने फिर जोर देना शुरू किया है। वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने हाल ही में पीओके के भारत के साथ एकीकरण पर भाजपा की प्रतिबद्धता रेखांकित की है। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व सर्मा शामिल हैं। सबसे पहले अमित शाह ने एक असाधारण घोषणा कर जोर दिया कि भारत पीओके पर अधिकार कर लेगा क्योंकि 'वह हमारा है।' इस बयान को एक साहसी राजनीतिक वादा कहा जा सकता है जो पीओके पर भाजपा का लंबे समय से दृष्टिकोण है। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व सर्मा ने यही भावना व्यक्त करते हुए जोर दिया कि यह कदम केवल भावनात्मक न हो कर वर्तमान सरकार के लिए यथार्थ लक्ष्य है। इसके बाद राजनाथ सिंह का थोड़ा अलग दृष्टिकोण सामने आया जिसमें उन्होंने पीओके में मानवाधिकारों की स्थिति पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का आह्वान किया कि वे इस क्षेत्र में मानवाधिकार उल्लंघनों पर गौर करें। वर्तमान लोकसभा चुनाव में ऐसे बयानों का अर्थ यह स्पष्ट संकेत है कि भाजपा काफी समय से लंबित इस मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहती है। पीओके का मुद्दा चुनाव विमर्श में शामिल करना पार्टी की रणनीति है जिससे वह राष्ट्रवादी तत्वों का समर्थन मजबूत करना चाहती है। वास्तव में पीओके में स्थिति अच्छी नहीं है। वहां स्थानीय जनता ज्यादा



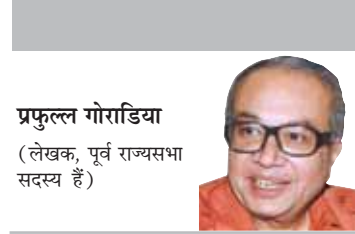
स्वायत्तता, राजनीतिक अधिकारों, ज्यादा स्वशासन तथा स्थानीय नियंत्रण की मांग कर रही है। उसे मानवाधिकार उल्लंघनों तथा नागरिक स्वतंत्रताओं पर बंधनों की भी चिन्ता है। जनता अपने मूलाधिकारों व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक दमन समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही आर्थिक विकास एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए बेहतर अवसरों, बेहतर ढांचागत संरचना, स्वास्थ्यरक्षा

और शिक्षा की जरूरत है। क्षेत्रीय विकास के लिए ज्यादा निवेश भी जरूरी है। इन कारणों से पीओके की जनता न केवल पाकिस्तान की केन्द्रीय सत्ता के दमन का विरोध कर रही है, बल्कि वह भारत में जम्मू कश्मीर की अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से अभूतपूर्व व असाधारण प्रगति से हतप्रभ है। हाल ही में उसने जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूर्व अलगाववादी तत्वों तक को शामिल होकर मतदान करते देखा है। ऐसे में उसका यह सोचना स्वाभाविक है कि यदि उसका क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे के बजाय भारतीय जम्मू कश्मीर में शामिल होता तो बहुत अच्छा होता। केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन स्थितियों को देखते हुए ही कहा है कि पीओके की जनता स्वयं भारत में शामिल होने की बात करेगी और यह प्रक्रिया संभवतः शुरू भी हो गई है।

पीओके के एक निर्वासित नेता ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह पीओके में मानवाधिकार उल्लंघनों का मामला अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने के साथ यह 'अवसर न चूके।' स्पष्ट रूप से वर्तमान स्थितियों में यदि पीओके की जनता और बड़ी संख्या में भारत में शामिल होने की मांग करे तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार अपने दायित्व से पीछे नहीं हटेगी। मोदी सरकार पाकिस्तान या उसके समर्थकों की धमकियों से डरने वाली नहीं है। भारत की सारी जनता भावनात्मक रूप से इस मामले में भाजपा के साथ खड़ी होगी।

समाप्त हुआ सांप्रदायिक टकराव

आलोचनाओं के बावजूद, मोदी के कार्यकाल में सांप्रदायिक टकराव के मामले न्यूनतम रहे हैं। सरकार ने सांप्रदायिक सद्भावना के लिए परस्पर समझदारी पर जोर दिया है।



प्रफुल्ल गोरडिया
(लेखक, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं)

आलोचनाओं के बावजूद, मोदी के कार्यकाल में सांप्रदायिक टकराव के मामले न्यूनतम रहे हैं। सरकार ने सांप्रदायिक सद्भावना के लिए परस्पर समझदारी पर जोर दिया है। वर्तमान लोकसभा चुनाव प्रचार में भी मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने इस आयाम पर बहुत जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्तमान लोकसभा के व्यापक चुनाव प्रचार अभियान में मुस्लिम समुदाय का आह्वान किया कि वह गंभीरता से 'आत्मावलोकन' करे। उन्होंने कांग्रेस की भी जम कर आलोचना की जो लगातार समाज में 'अलगाव' की भावना को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। जैसी कि उम्मीद थी, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में सीधे-सीधे अपनी बात कही है और कुछ कटु सत्य व तथ्य भी सामने रखे हैं। कोई भी तटस्थ व ईमानदार राजनीतिक विश्लेषक इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कार्यरत प्रशासन ने देश को सांप्रदायिक टकरावों से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और दिल्ली में 2020 में हुए दंगे इसका अपवाद हैं। इसके पहले सांप्रदायिक टकराव भारत में आमतौर से होते ही रहते थे। हालांकि, वर्तमान समय में गौर्वध की तस्करि को लेकर अपवाद स्वरूप कुछ सांप्रदायिक टकराव हुए हैं। गौर्वध एवं गौर्मांस के लिए गायों की तस्करि भारत में एक खास समुदाय के कुछ लोगों की प्रवृत्ति है। हिंदू हमेशा से गौर्वध की हत्या का पूरी ताकत करते रहे हैं। इससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं क्योंकि वे गाय को माता की तरह मान कर उसकी पूजा करते हैं। सोलहवीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर ने गौर्वध पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। भारत के



विभाजन में एक अलिखित समझौता यह भी था कि विभाजन के पश्चात भारत में रहने की इच्छा रखने वाले मुसलमानों को बचाव देने के प्रयास कर रही है। जैसी कि उम्मीद थी, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में सीधे-सीधे अपनी बात कही है और कुछ कटु सत्य व तथ्य भी सामने रखे हैं। कोई भी तटस्थ व ईमानदार राजनीतिक विश्लेषक इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कार्यरत प्रशासन ने देश को सांप्रदायिक टकरावों से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और दिल्ली में 2020 में हुए दंगे इसका अपवाद हैं। इसके पहले सांप्रदायिक टकराव भारत में आमतौर से होते ही रहते थे। हालांकि, वर्तमान समय में गौर्वध की तस्करि को लेकर अपवाद स्वरूप कुछ सांप्रदायिक टकराव हुए हैं। गौर्वध एवं गौर्मांस के लिए गायों की तस्करि भारत में एक खास समुदाय के कुछ लोगों की प्रवृत्ति है। हिंदू हमेशा से गौर्वध की हत्या का पूरी ताकत करते रहे हैं। इससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं क्योंकि वे गाय को माता की तरह मान कर उसकी पूजा करते हैं। सोलहवीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर ने गौर्वध पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। भारत के

विभाजन में एक अलिखित समझौता यह भी था कि विभाजन के पश्चात भारत में रहने की इच्छा रखने वाले मुसलमानों को बचाव देने के प्रयास कर रही है। जैसी कि उम्मीद थी, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में सीधे-सीधे अपनी बात कही है और कुछ कटु सत्य व तथ्य भी सामने रखे हैं। कोई भी तटस्थ व ईमानदार राजनीतिक विश्लेषक इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कार्यरत प्रशासन ने देश को सांप्रदायिक टकरावों से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और दिल्ली में 2020 में हुए दंगे इसका अपवाद हैं। इसके पहले सांप्रदायिक टकराव भारत में आमतौर से होते ही रहते थे। हालांकि, वर्तमान समय में गौर्वध की तस्करि को लेकर अपवाद स्वरूप कुछ सांप्रदायिक टकराव हुए हैं। गौर्वध एवं गौर्मांस के लिए गायों की तस्करि भारत में एक खास समुदाय के कुछ लोगों की प्रवृत्ति है। हिंदू हमेशा से गौर्वध की हत्या का पूरी ताकत करते रहे हैं। इससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं क्योंकि वे गाय को माता की तरह मान कर उसकी पूजा करते हैं। सोलहवीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर ने गौर्वध पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। भारत के

विभाजन में एक अलिखित समझौता यह भी था कि विभाजन के पश्चात भारत में रहने की इच्छा रखने वाले मुसलमानों को बचाव देने के प्रयास कर रही है। जैसी कि उम्मीद थी, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में सीधे-सीधे अपनी बात कही है और कुछ कटु सत्य व तथ्य भी सामने रखे हैं। कोई भी तटस्थ व ईमानदार राजनीतिक विश्लेषक इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कार्यरत प्रशासन ने देश को सांप्रदायिक टकरावों से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और दिल्ली में 2020 में हुए दंगे इसका अपवाद हैं। इसके पहले सांप्रदायिक टकराव भारत में आमतौर से होते ही रहते थे। हालांकि, वर्तमान समय में गौर्वध की तस्करि को लेकर अपवाद स्वरूप कुछ सांप्रदायिक टकराव हुए हैं। गौर्वध एवं गौर्मांस के लिए गायों की तस्करि भारत में एक खास समुदाय के कुछ लोगों की प्रवृत्ति है। हिंदू हमेशा से गौर्वध की हत्या का पूरी ताकत करते रहे हैं। इससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं क्योंकि वे गाय को माता की तरह मान कर उसकी पूजा करते हैं। सोलहवीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर ने गौर्वध पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। भारत के

मलयालम सुपरस्टार के जिहादी रिश्ते

इस विवाद ने एक तीखी राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है और केरल के राजनीतिक परिदृश्य में गहरे तनाव को उजागर कर दिया है।



कुमार चेलपन
(लेखक, दि पायनियर के विशेष संवाददाता हैं)

चेन्नई के व्यवसायी मोहम्मद शारशद, जो सीपीआई (एम) के कार्यकर्ता भी हैं, द्वारा यह खुलासा कि मलयालम सिनेमा के सुपर मेगा स्टार ममूटी ने केरल के धर्मनिरपेक्ष, उदार और लोकतांत्रिक राजनीतिक नेताओं को चौंका दिया है। सीपीआई (एम), सीपीआई और कांग्रेस के नेता ममूटी को जिहादी के रूप में चित्रित करने के लिए संघ परिवार के खिलाफ खूबकर सामने आए हैं। ममूटी के जिहादी संगठनों के साथ संबंधों के बारे में खुलासा एक मुस्लिम युवक, सीपीआई (एम) के स्थानीय नेता ने किया था। ममूटी के जिहादी संबंधों के बारे में रिपोर्ट के बारे में संघ परिवार पर हमला करने वाले पहले व्यक्ति केटी जलील

विधायक थे, जो सीपीआई (एम) के पूर्व मंत्री और प्रतिबंधित सिमा के पूर्व अध्यक्ष थे। जलील अपने भाषणों और लेखों के लिए प्रसिद्ध हैं कि भारत को केवल इस्लाम के माध्यम से ही आजाद कराया जा सकता है। फिर अन्य मंत्रियों ने इस मुद्दे को उठाया और इसने केरल में हलचल मचा दी। ममूटी, जो अपने कॉलेज के दिनों में एक औसत से भी नीचे के छात्र थे, महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से अरबी स्नातक हैं। जब वे छात्र थे, तब प्रोफेसर मुहम्मद अरबी विभाग के प्रमुख थे और वही प्रश्नपत्र तैयार करते थे और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते थे। उन दिनों महाराजा कॉलेज में कोई भी अरबी छात्र बीए अरबी परीक्षा में फेल नहीं हुआ था। सुपर मेगा स्टार को उपाधि एक पुरानी कहानत की याद दिलाती है कि अंधों के देश में एक आंध वाला ही राजा होता है। ममूटी हिंदी फिल्मों या हॉलीवुड के अपने समकक्षों से कहीं आगे हैं। जिहादी या सांप्रदायिक होना कोई अपराध नहीं है। यहां मुद्दा यह है कि जो मुस्लिम समुदाय

की संगठित सौदेबाजी क्षमता पर सवाल उठता है, वह केरल में अवांछित व्यक्ति बन जाता है। जो नेता मुस्लिम राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं के छिपे हुए एजेंडे को उजागर करने का साहस करते थे, वे कूड़ेदान में समा गए। ईएमएस नंबूद्रीपडु ऐसे लोगों की सूची में सबसे ऊपर हैं, जिन्हें इस्लामवादी नेताओं ने खत्म कर दिया। 1991 के विधानसभा चुनावों से पहले, ई के नयनार और एम वी राघवन (दोनों मार्क्स, लेनिन और स्टालिन से मिलने के लिए चले गए) जैसे कुछ सीपीआई (एम) नेताओं ने सुझाव दिया था कि पार्टी को मुस्लिम लीग के साथ ठठबंधन करना चाहिए। लेकिन नंबूद्रीपडु ने तुरंत जवाब दिया कि मुस्लिम लीग को सहयोगी माने जाने के लिए अपना नाम और झंडा (जो पाकिस्तानी राष्ट्रीय ध्वज जैसा दिखता था) हटा देना चाहिए। मुस्लिम लीग के नेता क्रोधित हो गए और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नंबूद्रीपडु को आकार में काट दिया जाए और सीपीआई (एम) ने उन्हें 1992 में महासचिव के

प्रतिष्ठित पद से हटा दिया। मुस्लिम समुदाय के नेताओं के गुस्से का शिकार होने वाले अगले व्यक्ति ए के एंटनी थे जो 2001 से 2004 की अवधि के दौरान मुख्यमंत्री थे। 2003 में मराड समुद्र तट पर हुए नरसंहार में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा आठ हिंदू मछुआरों की हत्या एंटनी के ऊपर हैं, जिन्हें इस्लामवादी नेताओं ने खत्म कर दिया। 1991 के विधानसभा चुनावों से पहले, ई के नयनार और एम वी राघवन (दोनों मार्क्स, लेनिन और स्टालिन से मिलने के लिए चले गए) जैसे कुछ सीपीआई (एम) नेताओं ने सुझाव दिया था कि पार्टी को मुस्लिम लीग के साथ ठठबंधन करना चाहिए। लेकिन नंबूद्रीपडु ने तुरंत जवाब दिया कि मुस्लिम लीग को सहयोगी माने जाने के लिए अपना नाम और झंडा (जो पाकिस्तानी राष्ट्रीय ध्वज जैसा दिखता था) हटा देना चाहिए। मुस्लिम लीग के नेता क्रोधित हो गए और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नंबूद्रीपडु को आकार में काट दिया जाए और सीपीआई (एम) ने उन्हें 1992 में महासचिव के

प्रतिष्ठित पद से हटा दिया। मुस्लिम समुदाय के नेताओं के गुस्से का शिकार होने वाले अगले व्यक्ति ए के एंटनी थे जो 2001 से 2004 की अवधि के दौरान मुख्यमंत्री थे। 2003 में मराड समुद्र तट पर हुए नरसंहार में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा आठ हिंदू मछुआरों की हत्या एंटनी के ऊपर हैं, जिन्हें इस्लामवादी नेताओं ने खत्म कर दिया। 1991 के विधानसभा चुनावों से पहले, ई के नयनार और एम वी राघवन (दोनों मार्क्स, लेनिन और स्टालिन से मिलने के लिए चले गए) जैसे कुछ सीपीआई (एम) नेताओं ने सुझाव दिया था कि पार्टी को मुस्लिम लीग के साथ ठठबंधन करना चाहिए। लेकिन नंबूद्रीपडु ने तुरंत जवाब दिया कि मुस्लिम लीग को सहयोगी माने जाने के लिए अपना नाम और झंडा (जो पाकिस्तानी राष्ट्रीय ध्वज जैसा दिखता था) हटा देना चाहिए। मुस्लिम लीग के नेता क्रोधित हो गए और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नंबूद्रीपडु को आकार में काट दिया जाए और सीपीआई (एम) ने उन्हें 1992 में महासचिव के

2010 में राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस मीटिंग के दौरान अच्युतानंदन ने कहा कि लव जिहाद एक वास्तविकता है। उन्होंने कहा था, मुस्लिम कट्टरपंथियों का एजेंडा अगले दो दशकों में केरल को मुस्लिम बहुल राज्य में बदलना है। हालांकि सीपीआई (एम) 2011 के चुनावों में मामूली अंतर से हारी थी, लेकिन पार्टी 2016 में पूरे केरल में अच्युतानंदन की सद्भावना का इस्तेमाल करते हुए सत्ता में लौट आई। कामरगोड से तिरुवनंतपुरम तक राजमार्ग पर अच्युतानंदन के बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए थे, जिससे यह आभास होता था कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के रूप में सीपीआई (एम) को पसंद वे ही होंगे। लेकिन पिनारई विजयन, जिनकी तस्वीरों या पोस्टर स्पष्ट रूप से गायब थे, को पार्टी के नेतृत्व द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया और तब से वे केरल के बेताज बादशाह बन गए हैं। अच्युतानंदन को सीपीआई (एम) में मुस्लिम समुदाय के प्रभाव के कारण दरकिनार नहीं किया गया। मुस्लिम लीग और समुदाय के नेताओं की नाराजगी ने

आप की बात

प्रवासियों का योगदान

हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रवासियों द्वारा वर्ष 2022 में देश में भेजा गया धन या रैमिटेन्स दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह भारतीय प्रवासियों की परिश्रम, दक्षता और मातृभूमि के प्रति श्रेष्ठ को दर्शाती है। उनके द्वारा भेजी 111 अरब डॉलर की राशि ने देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गर्व की बात है कि भारत विश्व का पहला देश बन गया है जहां प्रवासियों द्वारा एक साल में 100 अरब डॉलर से अधिक रकम भेजी गई है। यह रकम प्रत्यक्ष भेजी विदेशी निवेश-एफडीआई से भी ज्यादा है। लेकिन प्रवासी भारतीयों को विदेश में अनेक समस्याओं का

विस्तारवादी चीन

पाक अधिकृत कश्मीर- पीओके में चीन कुछ समय से ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा है। चीनी राष्ट्रवाधियों की मंशा शुरू से ही यथासंभव दुनिया के अन्य देशों की अधिकतम भूमि हड़पने की रही है। इसके चलते अपनी सीमा से सटे हुए लगभग सभी देशों के साथ उसका भूमि विवाद चल रहा है और अरुणाचल तक पर अपना अधिपत्य जता रहा है। ऐसे ही पाकिस्तान जैसे मूर्ख देश ने जब चीन को पीओके का एक भूभाग प्लेट में रखकर सौंप दिया तो वह इसका अधिकतम उपयोग अपने लाभ के लिए करने लगा है। इसका सबसे ज्यादा तनाव भारत को झेलना पड़ रहा है। अन्य छोटे देशों को भी वह कर्ज के जाल में फंसा कर धीरे-धीरे उन पर आधिपत्य जमाने ने में लगा हुआ है। छोटे देशों के कुछ नेता चीन से करीब नजराने प्राप्त कर उसकी गोद में जा बैठते हैं। मालदीव इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय राजनय को अपने पक्ष में करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। भारत सरकार को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अपना कद और बढ़ा करना होगा।

एनटीए की परीक्षा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी-एनटीए द्वारा ली जाने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का यह तीसरा साल है। उम्मीद थी कि पिछली गड़बड़ियों का निराकरण करते हुए इस साल सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन इस साल भी छात्रों को कई तरह की दिक्कतें उठानी पड़ीं। पहले 12वीं के मार्क्स पर कॉलेज में एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब उसके स्थान पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा शुरू की गई है। इससे देश के लाखों छात्रों को काफी फीस अलग से देनी पड़ती है। इसके साथ ही परीक्षाओं में भयानक अव्यवस्था व्याप्त है। इस बार भी परीक्षा केंद्र चुनिंदा बड़े शहरों में और कहीं-

कहीं शहरों से 30-40 किमी. दूर रखे गए। अनेक परीक्षा केंद्रों में भारी अव्यवस्थाओं के चलते छात्रों को काफी तकलीफ उठानी पड़ी। कुछ केंद्रों पर तो बिजली सप्लाई की भी समुचित व्यवस्था नहीं थी। इसके साथ ही छात्रों को इन शहरों में होटलों में रहने व भोजन आदि पर भी बहुत खर्च करना पड़ा। ऐसे में बेहतर होगा कि जहां 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं ली जाती हैं उन्हीं केंद्रों पर एनटीए की परीक्षाएं आयोजित की जाएं ताकि छात्रों का समय व धन बच सके और वह शांत मन से अपने घर पर परीक्षा की तैयारी कर सकें। उम्मीद है कि अधिकारी इस पर गौर करेंगे।

राजनेताओं की परीक्षा

चुनाव में कोई अपने खानदान की याद दिला रहा है तो कोई अपने पूर्वजों की तथाकथित कुरबानी, कोई कमर दर्द से परेशान होने के बाद भी लोकतंत्र बचाने में जुटा है तो कोई दोबारा जेल न जाने के लिए चोट मांग रहा है। जनता सोचती है कि कहीं संविधान और लोकतंत्र पर खतरे का भय दिखा कर विपक्ष देश को जातिगत रूप से तोड़ने में कामयाब तो नहीं हो जाएगा। इसके जवाब में किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना, खाद्य सुरक्षा, धारा 370 का उन्मूलन, अभिनन्दन की वापसी, बालाकोट हवाई हमला, राम मंदिर,

रैपिड रेत, काशी कोरिडोर, अटल टनल, उज्ज्वला योजना, तेज गति से होता राजमार्ग का निर्माण, प्रेट कोरिडोर और अन्य योजनाओं पर नजर डालें तो पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल संतोषजनक दिखाई पड़ता है। मतदाताओं में नाराजी व सहमति अनेकों मुद्दों पर हो सकती है। संभव है कि कुछ जगह वर्तमान सरकार चूक गई हो पर अंततः भारतीय जनता अपने विवेक से व्यापक तस्वीर तथा देश के भविष्य को देख कर फैसला देगी। देखा होगा कि राजनेता चुनाव की परीक्षा में कैसा प्रदर्शन करते हैं।

